No official in this case has been suspended so far as the Board of Directors in the NCCF decided for further action after receipt of Report from the CBI.

सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति

7569. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सुपर बाजार की वित्तीय स्थिति निरन्तर खराब होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सुपर बाजार द्वारा प्रतिवर्ष योजना-वार और कर्मचारियों पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(घ) प्रबंधन समिति द्वारा वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए और फिजूल खर्ची को रोकने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ; और

(ङ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं । इसकी बिक्री 1991-92 के 9784.01 लाख रुपए से बढ़कर 1993–94 में 11520.34 लाख रुपए पर पहुंच गई है और इसका शुद्ध लाभ 1991–92 के 9.33 लाख रुपए से बढ़कर 1993–94 में 41.65 लाख रुपये हो गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों पर, सुपर बाजार द्वारा यथासूचित व्यय निम्नवत है :—

(लाख रुपए में)

	1992–93	1993–94
स्थापना	741.06	825.21
ब्याज	20.36	30.02
किराया	33.38	29.87
प्रशासकीय व्यय	149.07	189.98

(घ) और (ङ) चूंकि सुपर बाजार को गत कई वर्षों से वित्तीय हानि नहीं हुई है, अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

खाद्य तेल

7570. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993–94 के दौरान देश में खाद्य तेलों का अनुमानतः कितना उत्पादन, आयात, निर्यात हुआ और उनकी कितनी खपत हुई ;

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान खाद्य तेलों के आयात-निर्यात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ;

(ग) देश में 1 अप्रैल, और 31 दिसम्बर, 1993 को खाद्य तेलों का भंडार कितना था; और

(घ) आयातित खाद्य तेल की लागत, बीमा भाड़ा लागत और निर्यात किये जाने वाले खाद्य तेल का निःशुल्क नौभार प्रभारों और इसका देश में औसत मूल्य कितना है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) तेल वर्ष (नवम्बर–अक्तूबर) 1993–94 के दौरान देश में खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन, 67.20 लाख मीटरी टन की अनुमानित मांग के मुकाबले 61.70 लाख मीटरी टन था । वित्तीय वर्ष 1993–94 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा 51,04 करोड़ रुपए मूल्य के 41,965 मी. टन खाद्य तेल का आयात किया गया था । वर्ष के दौरान यू.एस.एड के तहत राज्य व्यापार निगम को उपहार स्वरूप अपरिष्कृत सोयाबीन के तेल की भी 37,000 मी. टन मात्रा प्राप्त हुई थी सरकार की निर्यात और आयात नीति के तहत 5 कि. ग्रा. तक के उपभोक्ता पैकों में चुने हुए खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति है। निर्यात की मात्रा न्यूनतम है और निर्यात की गई वास्तविक मात्रा के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) राज्य व्यापार निगम के पास 1–4–1993 और 31–12–1993 को खाद्य तेल का स्टाक निम्नवत था :—

(मात्रा मी.टन में)

तारीख	आर.बी.डी. पामोलीन	अपरिष्कृत सोयाबीन तेल
1–4–93	5820	21917
31–12–93	32163	—

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेल की खरीद लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से की जाती हैं। इन प्रभारों में से प्रत्येक की कीमत अलग से उपलब्ध नहीं है । वस्तुओं जिनमें खाद्य तेल शामिल हैं, के निर्यात हेतु सेवा प्रभारों में अलग-अलग पत्तनों और भिन्न-भिन्न वस्तुओं के मामले में अन्तर होता है । प्रत्येक किस्म के लिए खाद्य तेलों के देशीय मूल्य भिन्न-भिन्न हैं ।

HRA case of BIS

7571. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that house rent allowance case of the employees of Bureau of Indian Standards is pending with Finance Ministry and Finance Ministry is awaiting for Vth Central Pay Commission recommendations; and

(b) if BIS does not come in purview of Vth Central Pay Commission then the reasons for the case being pending till Vth CPC recommendations?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) and (b) As BIS employees accepted a package of pay and allowances including HRA on the basis of Fourth Central Pay Commission recommendations. Ministry of Finance has advised to wait for Vth Central Pay Commission report before any change in the HRA is considered.

Laboratories of BIS

7572. SHRI MISA R. GANESAN: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that laboratories of Bureau of Indian Standards are well equipped and each machine costs lacs of Rupees;

(b) whether it is also a fact that some machines are not utilised even for a single day; and

(c) steps taken to commercialise BIS labs to earn more revenue?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir. Some of the equipments are highly specialised and costly.